



जीवन की सार्थकता उसकी सक्रियता में है

## चुनावों की अति

महाराष्ट्र और हरियाणा में नई सरकारों का समुचित तरीके से गठन होने के पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने से चुनावों के सिलसिले से छुटकारे की जरूरत एक बार फिर महसूस हो रही है। आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड विधानसभा के चुनाव करने की पहल क्यों नहीं हुई? इस सवाल का चाहे जो जवाब हो, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म होते ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव करीब आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव निकट आ जाएंगे। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। बार-बार होने वाले चुनाव केवल सरकारी खजाने पर बोझ ही नहीं बनते, वे शासन-प्रशासन के आवेग को भी बाधित करते हैं। इसी के साथ वे राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बहस हुई थी, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसका कारण यही रहा कि राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव पर अपेक्षित गंभीरता का परिचय नहीं दिया।

इसमें दोष नहीं कि लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव करने में कुछ समझौते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका समाधान नहीं हो सकता। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो ऐसा आसानी से किया जा सकता है। एक साथ चुनाव के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उनका महत्व एक सीमा तक ही है, क्योंकि आजादी के बाद एक असें तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। आखिर जो काम पहले होता रहा वह फिर क्यों नहीं हो सकता? एक साथ चुनाव को लेकर एक बड़ी दलील यह है कि ऐसा होने से क्षेत्रीय दलों को घाटा हो सकता है। इस दलील में कुछ वजन तो है, लेकिन इस कथित घाटे से बचने के लिए लोकसभा चुनाव के दो या तीन साल बाद सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इस तरह पांच साल की अवधि में देश को केवल दो बार ही चुनावों का सामना करना होगा-पहले लोकसभा चुनाव का और फिर विधानसभाओं के चुनाव का। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इस फार्मूले पर सहमत हों। चूंकि झारखंड नक्सली हिंसा से ग्रस्त है इसलिए यहाँ की 81 विधानसभा सीटों के लिए पांच चरणों में मतदान होगा। क्या छत्तीसगढ़ के मुकाबले झारखंड में नक्सलियों की चुनौती अधिक गंभीर है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि करीब एक साल पहले छत्तीसगढ़ में 72 सीटों के लिए दो चरणों में ही मतदान हुआ था। स्पष्ट है कि इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर नक्सली संगठन कब तक चुनाव प्रक्रिया के लिए सिरदर्द बने रहेंगे?

## चारधाम यात्रा

इस बार चारधाम यात्रा में रिकार्ड संख्या में पहुंचे तीर्थयात्रियों से उत्तराखंड सरकार के साथ ही स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। प्रदेश में वर्ष 2013 की आपदा के बाद यह सबसे सफलतम चारधाम यात्रा सीजन रहा। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस वर्ष केदारनाथ में 10 लाख 21 हजार यात्री, बदरीनाथ में अभी तक तकरीबन 12 लाख यात्री, गंगोत्री में पांच लाख 30 हजार यात्री और यमुनोत्री में चार लाख 66 हजार तीर्थयात्री पहुंचे। बदरीनाथ व केदारनाथ में पहुंची तीर्थयात्रियों की यह संख्या अभी तक का ऑल टाइम रिकार्ड है। इससे पहले कभी भी यहां इतनी संख्या में तीर्थ यात्री नहीं पहुंचे। यह निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए सुखद अहसास कला जा सकता है। इससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार सुश्रुति चारधाम यात्रा का संदेश देने में कामयाब रही है। अब इसके पीछे चाहे व्यापक प्रचार प्रसार की भूमिका रही है या फिर जनता में चारधामों के प्रति श्रद्धा की भावना, कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह प्रदेश के लिए खासा महत्वपूर्ण है। इससे देश-दुनिया में एक अच्छा संदेश भी गया है। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार मिला तो व्यापारियों को अच्छी आय हुई है। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से होते पलायन को रोकने में सहायक होगी। चारधाम यात्रा की सफलता पर जहां तालियां बजाई जा सकती हैं तो वहीं इसमें आ रही दिक्कतों पर भी नजर डालना जरूरी है। गंगोत्री व यमुनोत्री मार्ग पर लगातार होते भूस्खलन ने कई बार यात्री की रफ्तार को धीमा किया। इससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, बावजूद इसके इन स्थानों की समस्याओं का अब तक सही तरह से समाधान न किया जाना कहीं न कहीं यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाता है। इस समय श्रीनगर से त्रिभुक्तेश तक का मार्ग बहुत बेहतर नहीं है। भले ही ऑल वेदर रोड के निर्माण के कारण यह स्थिति आई है, लेकिन इसे दुरुस्त रखा जा सकता है। सफल चारधाम यात्रा के बीच कुछ दुर्घटनाओं ने भी ध्यान आकर्षित किया। सरकार को चाहिए कि वह इस तरह की दुर्घटनाओं का कारण बनी खामियों पर ध्यान दे। बड़ी संख्या में यात्रियों के आने से अब सुविधाएं बढ़ाए जाने की जरूरत भी महसूस हो रही है, जिस पर सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।

### जब तीर्थयात्रियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हो रही है तो सरकार को सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा

## बदलाव से ही मिलेगी मंजिल

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

**कौशल विकास से रोजगार सृजन की सरकारी मंशा तो सही है, पर इसे सफल बनाने के लिए कुछ सुधार भी करने होंगे**

पूरा एक नया तंत्र ही स्थापित कर दिया गया। अब तक करीब 334 क्षेत्रों में कौशल परिषद स्थापित की जा चुकी है। इनके तहत देश भर में कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं जो पशुपालन से लेकर वाहन, मोबाइल व कंप्यूटर ठीक करने का प्रशिक्षण देंगे। एक राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड भी स्थापित किया गया है। यानी अब सरकार लोगों को पंक्चर लगाता, जूते सिलता, बुनाई करना व पापड़ बनाने जैसे तमाम काम सिखा रही है और सीखने के एवज में पैसे भी दे रही है। केंद्र सरकार ने बौते आठ वर्षों में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से तमाम कॉर्पोरेट समूहों को रियायती दर पर 19,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं ताकि वे कौशल क्षमता का विकास करके युवाओं को व्यावहारिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें।

तमाम रपट बताती हैं कि इन कंपनियों ने इस रियायती मदद को अपने कारोबार में लगाने के अलावा बैंकों में रखकर ज्यादा प्रतिफल हासिल किया और अपने कंपनी समूह में कार्यरत प्रशिक्षुओं के खर्च में दिखाकर कानूनी बाध्याएं पूरी कर लीं। यानी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना केवल कागजों व प्रसार माध्यमों में ही अपना कौशल निखार रही है। दरअसल इस योजना में कुछ खामियां स्थापित की जा चुकी हैं। इनके तहत देश भर में कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं जो पशुपालन से लेकर वाहन, मोबाइल व कंप्यूटर ठीक करने का प्रशिक्षण देंगे। एक राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड भी स्थापित किया गया है। यानी अब सरकार लोगों को पंक्चर लगाता, जूते सिलता, बुनाई करना व पापड़ बनाने जैसे तमाम काम सिखा रही है और सीखने के एवज में पैसे भी दे रही है। केंद्र सरकार ने बौते आठ वर्षों में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से तमाम कॉर्पोरेट समूहों को रियायती दर पर 19,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं ताकि वे कौशल क्षमता का विकास करके युवाओं को व्यावहारिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें।

**गुलाम कश्मीर को लेकर भी हो पहल**  
गुलाम कश्मीर की कसक शीर्षक से लिखे अपने लेख में आर विक्रम सिंह ने गुलाम कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की पीड़ा के बहाने स्वतंत्र भारत के आरंभिक शासकों की गुलाम कश्मीर के मामले में अपनाई गई अक्षय अदूरदर्शिता का बेहतर निश्चलन से खाली न कराया जा सकता कि क्यों उन लोगों ने पाकिस्तानी कबायलियों को सफलपूर्वक मुँह धकेल रही भारतीय सेना को उड़ी में ही रोक दिया, जबकि आगे मुजफ्फराबाद का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था। इसके कारण फुँड को उड़ी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क, जो हाजीपूर दर्रे से होकर गुजरती है, सहित वर्तमान गुलाम कश्मीर पाकिस्तान से खाली न कराया जा सके। कश्मीर घाटी के प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर के इलाके, जो पंजाबी, पहाड़ी और गोत्री भाषी हैं, उन्हें भारत में मिलाया जाए, ताकि जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कश्मीर घाटी और उनका वर्चस्व बना रहे। पाकिस्तान से 1965 के युद्ध में हाजीपूर दर्रे को जीत लेने के बाद भी ताश्कंद में वार्ता की मेज पर हम इसे हार गए। ताश्कंद में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी की "रहस्यमय मृत्यु" क्या जीते हुए भूभाग को लौटाने के दबाव से उपजी हताशा का ही परिणाम था अथवा और भी कुछ, यह तो अभी भी उद्घाटित होना शेष है। अच्छी बात है कि अब गुलाम कश्मीर की वापसी की वचनौ हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी दिख रही है।

चंदन कुमार, देवघर

## मेलबाक्स

है, लेकिन इनमें बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। स्कूलों में कहीं शिक्षक नहीं हैं तो कहीं वे पढ़ाते नहीं। कहीं-कहीं तो शिक्षक होते हुए भी वे चाहेकर भी नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वे सरकार के तमाम सर्वे कार्यों में लगे होते हैं। वहीं बहुत से स्कूलों में संसाधनों का अभाव भी है। दूसरी तरफ सरकारी कर्म बच्चों को पास करने की नीति से भी परेशानी खड़ी हो रही है। एक तरह शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं और दूसरी तरफ उन्हें पास करना अनिवार्य होता है। ऐसे में शिक्षक औपचारिकता पूरी कर बच्चों को बिना ज्ञान के ही पास कर अगली कक्षा में प्रवेश दे देते हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में यही स्थिति है। ऐसे में जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे उनकी योग्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें न शिक्षक की गलती होती है और न ही बच्चों की, सारा दोष व्यवस्था का है। हमें प्राथमिक शिक्षा को साक्षरता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको भविष्य में आने वाली फसल के रूप में देखना चाहिए कि अच्छी फसल कैसे आए। प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राय सरकारों को प्राथमिक विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय के अनुरूप विकसित करना चाहिए, साथ ही शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

ऋषि भारद्वाज, नोएडा

## दलबदलू नेता

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जनता ने दल बदल करने वाले नेताओं को धूल चटा कर शुभ संदेश देने का



शंकर शरमा

जब तक हम अपनी भाषा में शिक्षण, लेखन, विमर्श नहीं करते तब तक उनके समकक्ष नहीं हो सकते जो अपनी भाषाओं में यह सब करते हैं

यह बात बार-बार साबित हो रही है कि जिन भारतीयों को पूरे देश से जुड़ाव-लगाव है वे तो हिंदी का महत्व समझते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय एकता के प्रति लापरवाह हैं, प्रायः वही हिंदी पर हीला-हवाला करते हैं। हमारे जो बुद्धिजीवी माओवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों आदि से सहनभूति रखते हैं, वे हिंदी का विरोध भी करते हैं। इसके विपरीत जो देश की धर्म-संस्कृति, एकता, अखंडता के प्रति समर्पित हैं, वे अपनी एक राष्ट्रीय भाषा का महत्व समझते हैं। इसे आरंभ से ही देख सकते हैं। ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास हुए थे। ये प्रयास कलकत्ता और बंबई से हुए थे, न कि इलाहाबाद या पटना से। इसके लिए मराठी तिलक महाराज, बंगाली बंकिम चंद्र और रवींद्रनाथ, तमिल सुब्रह्मण्यम भारती और गुजराती गांधी जैसे महारूपों ने प्रयास किए। नोट करें, अभी हिंदी की पैरोकारी करने वाले अमित शाह भी गुजराती हैं।

इतिहास दिखाता है कि हिंदी देश-प्रेम की भाषा रही है। वह किसी सीमित क्षेत्र की भाषा नहीं। इसीलिए इसके प्रति किसी क्षेत्र का अग्रह न था। न ही कोई क्षेत्र हिंदी को 'परदा' समझता था। वही स्थिति आज भी है। सविधान सभा में कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णामाचारी जैसे दक्षिण भारतीय दिग्गजों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। तब यह सहज बात समझी गई थी जिसमें देशप्रेम

की भावना थी। भारत में हिंदी किसी क्षेत्र विशेष की सीमित भाषा कभी नहीं थी। बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मलयाली, मराठी की तरह ही छत्तीसगढ़ी, कुमाऊंकी, गढ़वाली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगधी, अंगिका और मैथिली, आदि के सीमित प्रदेश हैं, किंतु हिंदी पूरे देश का स्वर है। यह शुरू से अभी तक देखा जा सकता है। महान कवि-चिंतक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन (अज्ञेय) के शब्दों में, हिंदी 'एक समग्र संस्कृति की संवाहिका' रही है। इसीलिए राष्ट्रीय भाषा का महत्व समझते हैं। इसे आरंभ से ही देख सकते हैं। ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास हुए थे। ये प्रयास कलकत्ता और बंबई से हुए थे, न कि इलाहाबाद या पटना से। इसके लिए मराठी तिलक महाराज, बंगाली बंकिम चंद्र और रवींद्रनाथ, तमिल सुब्रह्मण्यम भारती और गुजराती गांधी जैसे महारूपों ने प्रयास किए। नोट करें, अभी हिंदी की पैरोकारी करने वाले अमित शाह भी गुजराती हैं। इतिहास दिखाता है कि हिंदी देश-प्रेम की भाषा रही है। वह किसी सीमित क्षेत्र की भाषा नहीं। इसीलिए इसके प्रति किसी क्षेत्र का अग्रह न था। न ही कोई क्षेत्र हिंदी को 'परदा' समझता था। वही स्थिति आज भी है। सविधान सभा में कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णामाचारी जैसे दक्षिण भारतीय दिग्गजों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। तब यह सहज बात समझी गई थी जिसमें देशप्रेम



अवधेश राजपूत

परंतु देवनागरी में लिखने पर वह किसी को बांग्ला नहीं लगते। वही स्थिति गुजराती, तेलुगु, हिंदी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। पंजाबी, कन्नड़, उर्दू, आदि के साथ भी है। देवनागरी, देवनागरी, प्रचलित करने का प्रयास है। वह भारत के सभी भाषा-भाषियों के सम्मिलित योगदान से बनी है। उसकी कोई विशिष्ट या अलग शब्दावली नहीं है। इसीलिए वह पूरे भारत में बोली, समझी जाती है। वह या तो पूरे भारत की भाषा है या कहीं की नहीं है। यही हिंदी की पहचान और स्थिति है। इसीलिए भगत सिंह और अज्ञेय, दोनों ने कहा था कि देश में एक लिए, देवनागरी, प्रचलित करने का प्रयास करें तो राष्ट्रीय भाषा की समस्या स्वतः सुलझ जाएगी। देवनागरी में लिखी कोई भी भारतीय भाषा हर देशवासी की लिए सरल, सहज, सहल होगी। उस पर अधिकार करना मामूली बात होगी जो अंग्रेजी के लिए पूरा जीवन लगाकर भी अधिकांश के लिए संभव नहीं।

जहां तक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 'हिंदी समझना कौन?' का प्रश्न है तो उन्हीं मंचों पर जापानी, हिब्रू, जर्मन, अरबी और रूसी आदि भी बोली जाती हैं। जैसे उसे सभी समझते हैं, वैसे ही हिंदी भी समझेंगे। यानी समांतर अनुवाद

के प्रसारण से। यह दशकों पुरानी और मामूली, तकनीक है। कोई भाषा पूरी दुनिया में सभी नहीं समझते, लेकिन यदि बात महत्वपूर्ण हो तो दुनिया के कोने-कोने में उसे समझ लिया जाता है। जैसे, टैंगोर की गीतांजलि। अतः जरूरी यह है कि हम पहले भारत के हृदय की बात बोलें। ऐसी बात अपनी भाषा में ही बोली जा सकेगी। जब हम ऐसा बोलने लगेंगे तो दुनिया हमें उसी तरह सुनेगी, जैसे वह संस्कृत में उपलब्ध संपूर्ण ज्ञान भंडार को सदियों से सुनती-गुनती रही है। दुनिया में आज भी भारत की पहचान यहाँ की भाषा में लिखित उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योगसूत्र, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र आदि से है। नीरद चौधरी, राजा राव, खुशवंत सिंह जैसे लेखकों से नहीं। समाज की रचनात्मकता और मौलिकता अनिवार्यतः उसकी अपनी भाषा से जुड़ी होती है। दुनिया में मौलिकता का महत्व है, माध्यम का नहीं। इसलिए यदि स्वतंत्र भारत में मौलिक चिंतन, लेखन का हास होता गया तो अंग्रेजी के बोझ के कारण। मौलिक लेखन, चिंतन विदेशी भाषा में प्रायः असंभव है। कम से कम तब तक, जब तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की मूल सभ्यता की तरह

# प्रवासियों संग बदलती संस्कृति की छटा

जैसे सामाजिक समूह एक जगह से दूसरी जगह गांव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में विस्थापन करते हैं, वैसे ही संस्कृतियों भी विस्थापित होती हैं। इसी के साथ पर्व-त्योहार भी यात्राएं करते दिखते हैं। बहुसंस्कृतिक यानी कस्मोपोलिटन महानगरों यथा लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलकाता और दुबई में पर्व त्योहार एवं पूजा-पाठ से जाना जा सकता है कि उसे मनाने वाले समूह दुनिया के किस देश एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के निवासी हैं। आचार्य श्रुति मोहन सेन ने 1940-50 के कालखंड में 'संस्कृति संगम' नामक एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार भारत की विभिन्न जातियों एवं सामाजिक समूहों के लोग विस्थापित होकर देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाकर बसते गए। उनके पर्व-त्योहार और पूजा पद्धति से जाना जा सकता है कि वे मूलतः कहां के रहने वाले थे? अभी भी विस्थापन के साथ पर्व-त्योहारों के अनुगमन को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता के केंद्र में तो छठ पूजा का विशेष महत्व है ही, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता में भी समाहित है। इस पर्व में सूर्य की पूजा के साथ गंगा की अर्चना का भी विधान है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के विस्थापन के साथ ही यह त्योहार कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी पैठ बनाता गया और प्रवासियों की अस्मिता के प्रतीक के रूप में उभरा। इस पर्व को केंद्र में रखकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने-अपने शहरों में छठ पूजा समितियों और अन्य सामाजिक संगठन बना लिए हैं। धीरे-धीरे इन संगठनों से लग महानगरों के भी अनेक समूह जुड़ते

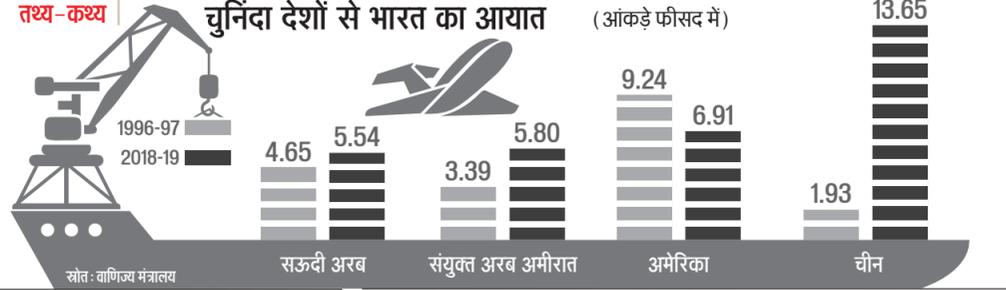


वद्री नारायण

जब लोग विस्थापन करते हैं तो उनके साथ उनकी परंपराएं भी विस्थापित होती हैं और संस्कृति भी

गा। मुंबई में छठ पूजा समितियों में महाराष्ट्र के लोगों की सहभागिता देखी जा सकती है। अनेक मराठी परिवार छठ पूजा में शामिल होकर व्रत भी करते हैं। वैसे तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि के लोग अपने गांव-घर लौटकर वहीं छठ पूजा करना चाहते हैं, किंतु समय की कमी और दूसरी व्यवस्था के कारण वे अपनी कर्मभूमि बने महानगरों में ही अपने छठ व्रत संपन्न कर लेते हैं। दिल्ली की यमुना नदी, प्रयाग के गंगा घाट, लखनऊ की गोमती, मुंबई के समुद्र तट, गुयाना की कोरेंटाइन नदी प्रवासियों के प्रसार के कारण छठ पूजा स्थल में तब्दील हो जाती है। चाहे यमुना तीरे हो या कोरेंटाइन का किनारा या फिर गोमती तट, यहाँ छठ गीत गाती महिलाएं एक तरह से गंगा से ही संवाद कर रही होती हैं। प्रवासियों के साथ फैल रहे पर्व-त्योहार उनकी सकारात्मक अस्मिता सुजित करते हैं। पर्व-त्योहार अपने संग पूजा-पाठ के साथ-साथ संगीत, लोक संस्कृति, लोकगीत, सबको स्वयं में गूंथे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करते पाए जाते हैं। प्रवासी जहां बसते हैं वहां उनके पर्व-त्योहार अपने

response@jagran.com



स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण सुझावों को इन्हें व्यवस्थाओं के तहत अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके अरबों रुपये के बजट को झोंक कर पूरा का

हमारी अधिकांश सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव पर चल रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी यही कहानी है। मोदी सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे का हाल में और विस्तार किया गया है। इसकी बजटीय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब हस्तकरवा, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और चटाई बुनने जैसे तमाम कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 कौशल परिषदों की स्थापना बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान भारी-भरकम भत्ते आदि की व्यवस्था भी की गई है। वैसे इससे मिलती-जुलती और भी पहल की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बीच तमाम समितियों का गठन किया गया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के